Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अप्रैल (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- गोंडा के पाँच रेलवे स्टेशनों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ 3
- प्रोजेक्ट अलंकार से हाईटेक होंगे वाराणसी के सात राजकीय विद्यालय 3
- बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा (बैंगन) और चंदौली का आदमचीनी चावल को मिला जीआई टैग 4
- मंगलायतन विश्वविद्यालय को मिला नैक ए प्लस ग्रेड 4
- 'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना' 5
- मुख्यमंत्री ने सुथनी में किया बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास 6
- मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को दी एक हज़ार करोड़ रुपए की सौगात 6
- चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा 7
- उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को मंजूरी दी 8
- प्रदेश के शहरों में सभी जरूरी स्थानों पर मिलेगी ई-चार्जिंग की सुविधा 8
- प्रदेश में बसेगी आईटी, मेडिसिटी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी 8
- एनएमएनएच और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये 9
- उत्तर प्रदेश के दो पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 10
- लखनऊ और हरदोई ज़िलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ 10
- गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय 12
- वाराणसी से प्रयागराज के बीच क्रूज संचालन के लिये सर्वे पूर्ण 12
- वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 13
- केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर काशी में दौड़ेगी वाटर टैक्सी 13
- एएएन अवार्ड 2023 से सम्मानित हुए बीएचयू के दो न्यूरो डॉक्टर 14
- उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालयों से हटाए जाएंगे सभी पुरुष स्टाफ 15
- उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच हुआ समझौता 15

नोट :

उत्तर प्रदेश

गोंडा के पाँच रेलवे स्टेशनों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2023 को पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि 'अमृत भारत स्टेशन योजना'के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के पाँच रेलवे स्टेशनों - मनकापुर, कटरा, बभनान, कर्नलगंज व छपिया को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।

प्रमुख बिंदु

- 'अमृत भारत स्टेशन योजना'के तहत चयनित पाँचों जंक्शन पर शॉपिंग काम्प्लेक्स, होटल, पार्किंग की उच्चस्तरीय एवं आधुनिक सुविधाएँ देने की तैयारी है। चयनित स्टेशन में आधुनिक प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हाल व रिटायरिंग रूम बनाया जाएगा। यात्री प्रतीक्षालय को बढ़ा कर उसे अन्य प्रतीक्षालयों से जोड़ा जाएगा।
- स्टेशन तक मार्गों का चौड़ीकरण, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिये विशेष शौचालयों की संख्या बढ़ाते हुए रेल यात्रियों को वाई-फाई सुविधा मुफ्त दी जाएगी।
- स्टेशन के नाम के कम से कम दो एलईडी बोर्ड लगेंगे तथा इनके प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रख वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिये विशेष स्थान बनाए जाएंगे।
- हरियालीयुक्त रेलवे स्टेशन के भवन भी दूर से ही आकर्षित करेंगे। साथ ही, स्थानीय कला व संस्कृति का संदेश-परक डिजाइन चित्रकारी द्वारा सुंदरीकरण करने से लोगों को स्टेशन पहुँचने पर उस क्षेत्र की विशेषता का भी एहसास होगा।
- छपिया स्टेशन पर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति लगाने व उनसे जुड़ी चित्रकारी की जाएगी। मनकापुर, कटरा, बभनान, कर्नलगंज रेलवे स्टेशनों को विकसित कर वहाँ की खासियत का एहसास कराते हुए सुंदर बनाया जाएगा।
- सभी स्टेशनों पर 'एक स्टेशन एक उत्पाद'के लिये न्यूनतम दो स्टाल, बेहतर कैफेटरिया व फाइव-जी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

प्रोजेक्ट अलंकार से हाईटेक होंगे वाराणसी के सात राजकीय विद्यालय

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि 'प्रोजेक्ट अलंकार'के तहत वाराणसी ज़िले के सात राजकीय हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिये कार्यदायी एजेंसी के साथ एमओयू की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी ज़िले के इन राजकीय हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से दो करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही विद्यालयों में जीर्णोद्धार व नवीनीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा।
- विद्यालयों के जर्जर भवनों की हालत को सुधार कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट अलंकार की ओर से राजकीय विद्यालयों को सँवारने के लिये 12 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग कक्षाएँ, प्रयोगशाला, खेल मैदान, बैंडमिंटन, वॉलीबाल कोर्ट, ओपन जिम के साथ मल्टीपर्पज हॉल, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के साथ सोलर प्लांट व रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

नोट :

बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा (बैंगन) और चंदौली का आदमचीनी चावल को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

3 अप्रैल, 2023 को जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. रजनीकांत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा (बैंगन) और चंदौली का आदमचीनी चावल के साथ अन्य 7 उत्पादों को जीआई सर्टिफिकेट मिला है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जीआई टैग यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर नाम खास तौर से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है।
- धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी जीआई हब के रूप में उभरी है। यहाँ के खास बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भाटा (सफेद बड़ा गोल बैंगन) और आदमचीनी चावल (ज़िला चंदौली) को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (Geographical Indications) एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का तमगा मिला है।
- जीआई विशेषज्ञ ने बताया कि नाबार्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के 11 उत्पादों को इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें 7 उत्पाद ओडीओपी (one district one product) में भी शामिल है और 4 कृषि एवं उद्यान से संबंधित उत्पाद काशी क्षेत्र से है। इनकी कुल संख्या अब 45 हो गई है।
- इस माह के अंत तक 9 और उत्पादों को जीआई टैग मिलने की उम्मीद है।

मंगलायतन विश्वविद्यालय को मिला नैक ए प्लस ग्रेड

चर्चा में क्यों ?

04 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (नैक) ने ए प्लस (NAAC A+) ग्रेडिंग प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि नैक की पाँच सदस्यीय टीम ने 22 से 24 फरवरी तक विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था। टीम ने विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं अनुसंधान गुणवत्ता के साथ प्रशासनिक व ढाँचागत व्यवस्था का भी मूल्यांकन किया था और विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों एवं अभिभावकों के साथ ही स्टाफ के साथ बैठक कर चर्चा की थी एवं फीडबैक भी लिया था।

नोट :

- विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने बताया कि अक्टूबर 2022 में सेल्फ एसेसमेंट रिपोर्ट (एसएसआर) नैक में सबमिट की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि नैक मूल्यांकन किसी भी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता जाँचने के लिये होता है। संस्थान द्वारा नैक ग्रेडिंग के लिये आवेदन करना होता है, आवेदन करने के बाद नैक की टीम संस्थान का निरीक्षण करती है। टीम शैक्षणिक सुविधाएँ, अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि व्यवस्थाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। इसी के आधार पर ग्रेड दिया जाता है।
- इसका काम देशभर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परखना और उनको रेटिंग देना है। नैक ग्रेडिंग से विद्यार्थियों को संस्थान का चयन करने में शिक्षा की व्यवस्था, अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे के लिये बेहतर विकल्प की सुविधा मिलती है।

'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना'

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की 'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना'के तहत सरकार ने प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी है। शहरों में पाँच किलोवाट कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधे हार्स पावर पर 400 और एक हार्स पावर पर 800 रुपए देना होगा। गाँवों में यह क्रमश: 300 और 600 रुपए होगा।
- इस योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। वहीं, हथकरघा पर 80 और पावरलूम लगाने पर 60 फीसदी तक अनुदान मिलेगा।
- पाँच किलोवाट अधिक भार वाले पावरलूम कनेक्शन-धारकों को 700 रुपए प्रति हार्स पावर, अधिकतम 9100 रुपए हर माह अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान को बिल में कम कर दिया जाएगा।

- वहीं, सूक्ष्म, लघु उद्यम निर्यात प्रोत्साहन तथा खादी ग्रामोद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। बेरोज़गार को रोज़गार से जोड़ने के लिये 'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना' शुरू की गई है। बुनकरों को हथकरघा के दो अनुमानित मूल्यों पर 50 हज़ार रुपए और 80 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

नोट :

- निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को बोनस नहीं देने वाले नियोक्ता को अब जेल नहीं होगी। इस प्रस्ताव के तहत बोनस संदाय अधिनियम-1965 में संशोधन को मंजूरी देते हुए छह माह तक सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- नए प्रावधान के तहत जुर्माने की राशि जो एक हज़ार रुपए थी, उसे बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया गया है। इसमें भी शमन की व्यवस्था दी गई है।
- विदित है कि अब तक कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता को छह माह की सजा या 1000 रुपए जुर्माना अथवा सजा व जुर्माना दोनों लगाए जाने का प्रावधान था।

मुख्यमंत्री ने सुथनी में किया बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले के सहजनवाँ तहसील के सुथनी गाँव में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से बनने वाले प्लांट का लखनऊ से वर्चुअल शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्लांट का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई की कंपनी एवरइन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। काम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर होगा।
- इस प्लांट में शहर से निकलने वाले गीले कूड़े से बायो सीएनजी गैस के अलावा खाद भी तैयार होगी। नगर निगम की टीम शहर से निकलने वाले गीले कूड़े को प्लांट तक पहुँचाएगी। प्लांट में लगी मशीनों के जरिए कूड़े की छँटाई होगी। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार प्लांट में सीएनजी और खाद तैयार होगी।
- बायो सीएनजी प्लांट में रोज़ाना 200 टन गीले कचरे की ज़रूरत होगी। इस कचरे से रोज़ाना 1000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। साथ ही, 40 टन जैविक खाद भी बनेगी। इससे महानगर से रोज़ाना निकलने वाले 350 टन में से ज्यादातर कूड़े का निस्तारण हो जाएगा।
- इस प्लांट को लगाने से लेकर संचालन तक का पूरा खर्च मुंबई की कंपनी एवरइन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड वहन करेगी यहाँ तक कि प्लांट में लगे कर्मचारियों को वेतन आदि भी कंपनी ही देगी।
- वहीं, नगर निगम को केवल ज़मीन उपलब्ध कराएगी इस ज़मीन के एवज में प्लांट संचालन करने वाली कंपनी प्रत्येक साल रायल्टी के रूप में नगर निगम को 56 लाख रुपए भी देगी। 15 साल के बाद कंपनी चालू हालत में नगर निगम को यह प्लांट सौंप देगी।
- नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय चौहान ने बताया कि एक साल में कंपनी इस प्लांट को तैयार कर लेगी। इसके बाद शहर का कूड़ा वहाँ गिरने लगेगा। फिर बायो सीएनजी के अलावा जैविक बनना शुरू हो जाएगा।
- कंपनी इस बायो सीएनजी और जैविक खाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करेगी। वह इसे बाज़ार में बेचेगी और अपना खर्च निकालेगी। हालाँकि नगर निगम को दोनों चीजें कुछ कम कीमत पर मिलेंगी।
- विदित है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी कंपनी के द्वारा प्लांट लगाया गया है और इससे वह अपना पूरा खर्च निकालती है।

मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को दी एक हज़ार करोड़ रुपए की सौगात

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के तीसरे दिन गोरखपुर को एक हज़ार करोड़ से अधिक रुपए की सौगात दी। उन्होंने हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (खाद कारखाना) के मैदान पर करीब 1046 करोड़ रुपए की लागत वाले 258 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 333.85 करोड़ रुपए के 56 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 711.81 करोड़ रुपए के 202 विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

नोट :

- गौरतलब है कि एक दिन पूर्व 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप बस रहे औद्योगिक गलियारे में गीडा के सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेज के 1071 करोड़ रुपए के निवेश से लग रहे प्लांट का भूमि पूजन व शिलान्यास किया था।
- वरुण बेवरेजेज के प्लांट में आम, अमरूद, लीची जैसे फलों व दूध की आपूर्ति करके किसान और पशुपालक अपनी आय कई गुना बढ़ा सकेंगे।
- गोरखपुर के प्लांट से 1500 नौजवानों को रोज़गार मिलेगा तथा दस हज़ार ग्रामीण अतिरिक्त आमदनी स्रोत से जुड़ेंगे।

चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में आठ सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की पार्टी से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इस आदेश के बाद अब रालोद एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले दल को कुल वोटों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करने पर राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जा सकती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने आठ सीटों पर जीत हासिल की थी, हालाँकि उसे महज 2.85 प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ था। इसी तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी और उसे महज 1.69 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे।
- वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी हैं। इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने की थी।
- विदित है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन किया था और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से आठ सीटों पर विजय प्राप्त की थी।
- गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया है। वहीं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया गया है।
- साथ ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।
- दरअसल चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इस समय देश में जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बाँटा गया है-
  - राष्ट्रीय पार्टी: जिन्हें चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। भारत में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं।
  - क्षेत्रीय पार्टी: जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो। भारत में अभी 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं।
  - गैर मान्यता प्राप्त पार्टी: ऐसी पार्टियाँ जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती हैं या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किये होते कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। अब रालोद भी इसी कैटेगरी में आ गई है।

नोट :

उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ की खरीद होगी।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6 हज़ार केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी।
- कुल 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को गेहूँ की बिक्री के लिये खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- विदित है कि प्रदेश में एक अप्रैल से गेहूँ की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। हालाँकि, सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी गेहूँ की आमद काफी कम है।
- चावल पर काम कर रहे चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी को अब और अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। इसके लिये कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी चावल पर अच्छा काम कर रहा है। काला नमक चावल पर किया गया अनुसंधान और इसका कार्य प्रशंसनीय रहा। ऐसे में इसे और विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस संस्थान को अब 0.97 हेक्टेयर ज़मीन और दी जाएगी।

प्रदेश के शहरों में सभी जरूरी स्थानों पर मिलेगी ई-चार्जिंग की सुविधा

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में लीडर बनाने के लिये काम शुरू कर दिया गया है। शहरों में सभी ज़रूरी स्थानों पर ई-चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कर रहे नागरिकों को सभी ज़रूरी स्थानों पर समुचित चार्जिंग की सुविधा भी देना है।
- इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। उसने ई-चार्जिंग सुविधाओं के लिये सेवा प्रदाताओं को ज़रूरत के आधार पर ज़मीन देनी की प्रक्रिया भी तय कर दी है।
- पहले चरण में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीईएमपी) को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 नगर निगम वाले शहरों में लागू किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिये कार्यकारी समूह का भी गठन किया गया है।
- प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि चार्जिंग के लिये सरकारी संस्थाओं को ज़मीन 10 वर्ष के पट्टे या लीज पर दी जाएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिये विद्युत मंत्रालय के मानकों के अनुसार निर्धारित रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा।
- पट्टा अवधि, रेवेन्यू शेयरिंग रेट व अन्य निर्धारित मानकों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। संस्थाओं का चयन टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क पर चार्जिंग की सुविधा देने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रदेश में बसेगी आईटी, मेडिसिटी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश में बंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी व महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी बसाने जा रही है। बेहतर शिक्षा हेतु एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी भी बसाए जाएंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार इसकी जिम्मेदारी आवास विभाग को दी गई है। वह इसके लिये भवन विकास उपविधि में व्यवस्था करने के साथ ही नीति लाने जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के 50 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
- राज्य सरकार कि योजना है कि देश दुनियाँ की नामी-गिरानी दवा कंपनियों के लिये ऐसा स्थान विकसित किया जाए जहाँ पर सभी सुविधाएँ हों, इसके लिये महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी बसाने की योजना है। इसके लिये कम से कम 200 से 300 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था की जाएगी।
- सभी प्रमुख शहरों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े कालेज और विश्वविद्यालय खोलने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।
- इसके साथ ही बंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी बसाने का खाका खींचा जा रहा है। विदित है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की गई थी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक यह पर्याप्त नहीं है। इसीलिये राज्य राजधानी क्षेत्र में इसके लिये खास इंतजाम किये जाएंगे।
- मेडिकल सिटी और आईटी सिटी के सहारे हर साल 50 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देश में अभी आईटी सेक्टर में सर्वाधिक नौकरियाँ बंगलुरु और पुणे में है।
- राज्य सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही अच्छी शिक्षा मिलने के साथ ही रोज़गार के संसाधन मिल सकें। इसीलिये आईटी सिटी खोलने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। मेडिकल सिटी में इससे जुड़े क्षेत्र में रोज़गार के द्वार खुलेंगे।
- विदित है कि वर्ष 2016 में लखनऊ में आईटी सिटी का शुभारंभ किया जा चुका है। लखनऊ-सुलतानपुर रोड पर 100 एकड़ में आईटी सिटी की स्थापना की गई है। यहाँ एचसीएल काम कर रही है। आईटी सिटी के जरिये लगभग 5000 लोगों को रोज़गार मिला है।
- गौरतलब है कि देश का पहला मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के इंद्रायणी में 300 एकड़ में बसाया जा रहा है। इसमें अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, दवा फैक्ट्रियाँ, वेलनेस व फिजियोथेरेपी केंद्र आदि होते हैं।

एनएमएनएच और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच), नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में मिलकर कार्य करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की निदेशक नाज रिजवी और राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक डॉ. आनंद कुमार सिंह ने पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में हस्ताक्षर किये।
- इस एमओयू के तहत प्रकृति के प्रति जागरूकता जगाने हेतु स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिये कार्यक्रम आयोजित करने के बहुआयामी प्रयास किये जाएंगे।
- राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच):
  - इसकी स्थापना देश की प्राकृतिक विरासत पर जागरूकता को चित्रित करने और बढ़ावा देने के लिये भारत की स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में से एक के रूप में की गई थी।
  - पर्यावरण शिक्षा के लिये समर्पित यह संस्थान मुख्य रूप से विषय-आधारित प्रदर्शनी दीर्घाओं, अनुभवात्मक संसाधन केंद्रों जैसे कि डिस्कवरी कक्ष, गतिविधि कक्ष और शैक्षिक एवं आउटरीच गतिविधियों से संपन्न है।
  - इसका उद्देश्य देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और प्राकृतिक इतिहास (भू-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान) को चित्रित करना है।
  - राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है।

नोट :

- एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दायित्व पूरे देश में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना और संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये एनएमएनएच ने देश के दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में अपने चार क्षेत्रीय संग्रहालयों के माध्यम से अपनी सेवाओं और अपने दृष्टिकोण को एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच के लिये विस्तारित किया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक आगामी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा।

- राज्य संग्रहालय, लखनऊ
  - राज्य का एक प्रतिष्ठित और सबसे पुराना बहुउद्देश्यीय संग्रहालय है जिसमें पुरातत्त्व, प्राकृतिक इतिहास, सजावट, कला और मुद्राशास्त्र से संबंधित कलाकृतियों का अद्भुत संग्रह है।
  - कलाकृतियों के संरक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रकाशन के साथ-साथ, संग्रहालय समय-समय पर अस्थायी/स्थायी प्रदर्शनी दीर्घाओं, तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये कार्यशालाओं, बुद्धिजीवियों/शोधकर्त्ताओं के लिये सेमिनार, कला प्रशंसा पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
  - राज्य संग्रहालय, लखनऊ देश के अन्य संग्रहालयों के सहयोग से देश और दुनिया की समृद्ध विरासत के संदर्भ में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्य करता है।

उत्तर प्रदेश के दो पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023

चर्चा में क्यों ?

17 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की दो ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- सिद्धार्थनगर ज़िले के भँवापुर ब्लाक की ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
- ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को यह पुरस्कार 'बाल हितैषी पंचायत'की श्रेणी में प्रदान किया गया है।
- वहीं मुरादाबाद ज़िले के दिलारी ब्लाक के ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) प्रदान किया गया।
- निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये गए-
  - व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिये दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)
  - सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी)
  - ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार
  - कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार।

लखनऊ और हरदोई ज़िलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- लखनऊ में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में 'PM MITRA योजना'के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु MoU हस्ताक्षरित हुआ।

नोट :

- पीएम मित्र पार्क लखनऊ को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.)/मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि में इसका रखरखाव भी करेगा।
- पीएम मित्र पार्क लखनऊ का कुल क्षेत्रफल 1,000 एकड़ होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है और इससे एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होने की उम्मीद है।
- पीएम मित्र पार्क लखनऊ ज़िले के मलिहाबाद ब्लॉक के अटारी गाँव में विकसित किया जा रहा है, जो सड़क, रेल और हवाई संपर्क से देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पार्क का निकटतम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कानपुर है, जो पार्क से 95 किलोमीटर की दूरी पर है।
- पीएम मित्र पार्क लखनऊ में एक इनक्यूबेशन केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण गृह, एक सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र और डिजाइन केंद्र और परीक्षण केंद्र एवं अन्य वस्त्र संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार सामान्य अवसंरचना का विकास करने के लिये पीएम मित्र पार्क लखनऊ को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी।

- पीएम मित्र पार्क लखनऊ कपड़ा उद्योग क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये मजबूती प्रदान करेगा।
- विदित है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में एक सफल वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 33 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसमें से 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव कपड़ा क्षेत्र के लिये है।
- भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय, पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है।
- यह प्रोत्साहन राशि, इकाई के कुल वार्षिक टर्नओवर का तीन प्रतिशत होगी, जिसकी सीमा प्रति कंपनी के हिसाब से निम्नलिखित होगी-
  - 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का निवेश- एक एंकर निवेशक कंपनी के लिये कुल प्रोत्साहन पर 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और अधिकतम 30 करोड़ रुपए की सीमा।
  - 100-300 करोड़ रुपए का निवेश- एक निवेशक कंपनी के लिये कुल प्रोत्साहन पर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और अधिकतम 15 करोड़ रुपए की सीमा।

नोट :

- अन्य निवेशक कंपनियाँ और ठेकेदार- एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और कुल प्रोत्साहन पर अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए, लेकिन उनके पास 100 या उससे ज्यादा लोगों का रोज़गार होना चाहिये।

- उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के अनुसार, पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित विनिर्माण इकाइयों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।
  - पीएम मित्र पार्क में स्थापित और न्यूनतम 50 लोगों को रोज़गार देने वाली इकाइयों के लिये पाँच वर्षों तक 2 रुपए प्रति यूनिट (60 लाख रुपए प्रति वर्ष तक) की बिजली टैरिफ सब्सिडी।
  - पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित विनिर्माण इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट।
  - मास्टर डेवलपर को बिजली तक पहुँच की खुली अनुमति।

गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को मंडलायुक्त गोरखपुर रवि कुमार एनजी ने बताया कि सीएसआर के तहत गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएँ उपलब्ध होगी।

प्रमुख बिंदु

- सीएसआर के तहत करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर ज़िले में प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
- इस विश्वविद्यालय में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होगी। बालिकाओं के उत्थान के लिये जरूरी सुविधाओं के आकलन हेतु कंसल्टेंसी फर्म को जिम्मेदारी दी गई है।
- गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से लिया गया है, जिसको लेकर कंपनी के अधिकारियों ने गोरखपुर का दौरा भी किया था।
- इस महिला विश्वविद्यालय के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा 100 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी और इसका संचालन भी कंपनी की ओर से किया जाएगा।
- विदित है कि गोरखपुर में पहले से चार विश्वविद्यालय संचालित हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय शामिल हैं। महिला विश्वविद्यालय बन जाने से गोरखपुर में पाँच विश्वविद्यालय हो जाएंगे।
- गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य कंपनी का फोकस महिलाओं के उत्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये सुविधाओं की काफी ज़रूरत है। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने में यह विश्वविद्यालय काफी कारगर साबित होगा।

वाराणसी से प्रयागराज के बीच क्रूज संचालन के लिये सर्वे पूर्ण

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2023 को भारतीय अंतर-देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक एल.के. रजक ने बताया कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा के संचालन के लिये भारतीय अंतर-देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी-प्रयागराज के बीच सर्वे पूरा कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- एल.के. रजक ने बताया कि जुलाई में इसे शुरू करने की तैयारी है। ट्रायल सफल रहा तो इस रूट पर जलयान की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मालवाहक जलयान के संचालन की भी योजना है।
- वाराणसी और प्रयागराज के बीच चलने वाला क्रूज सैलानियों को गंगा दर्शन के साथ ही पर्यटक स्थलों की भी सैर कराएगा।

नोट :

- इस सर्वे में कई जगहों पर जल परिवहन की बाधाओं को चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी सहित पर्यटन स्थलों पर जेटी का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रयोग के सफल होने के बाद जलमार्ग प्राधिकरण क्रूज सेवाओं में बढ़ोतरी भी करेगा।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रयागराज और वाराणसी के बीच के सभी पर्यटक स्थलों को जोड़ते हुए जलमार्ग प्राधिकरण नया रूट तैयार करने में जुटा है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी होने वाली एक तरफ की यात्रा को पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के जरिये संचालित करने की योजना है।
- इसके लिये कई निजी कंपनियों ने योजना में रुचि भी दिखाई है। इसमें निजी कंपनी के चयन के बाद किराया और अन्य सुविधाओं पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें वाराणसी से चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी और प्रयागराज में जेटी का निर्माण कर यहाँ ठहराव की व्यवस्था की जाएगी।
- इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये जलमार्ग प्राधिकरण स्थानीय प्रशासन से अपनी कार्ययोजना साझा करेगा। दरअसल, पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी प्रयागराज के बीच नए क्रूज संचालन के जरिये चुनार का किला, माँ विंध्यवासिनी धाम और सीता समाहित स्थल तक पहुँचने के लिये गंगा घाटों का विकास भी किया जाएगा।
- पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी को जलमार्ग का नया केंद्र बनाया जा रहा है। रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। वाराणसी से हल्दिया तक मालवाहक जलयान का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज के जरिये दुनिया के सबसे लंबे नदी मार्ग से वाराणसी का जुड़ाव किया गया है। प्रयागराज तक क्रूज संचालन के जरिये वाराणसी को केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजातालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी में बनने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। इसका निर्माण भी इसी तर्ज पर कराया जाएगा। ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिये यूपीसीए की ओर से निर्माण कंपनी के चयन हेतु टेंडर भी जारी कर दिया गया है।
- ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड डिजाइन (इंजीनियरिंग, सामानों की खरीद और डिजाइन) मोड पर काम के लिये कंपनी का चयन किया जाएगा।
- ऑनलाइन जारी टेंडर में कंपनियाँ यूपीसीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगा सकती हैं। बोली लगाने वाली कंपनियों को सुरक्षा राशि के तौर पर पाँच करोड़ रुपए जमा करने होंगे।
- टेंडर की शर्त के अनुसार जिस भी कंपनी का चयन किया जाएगा, उसे 30 महीने यानी ढाई साल में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर यूपीसीए को हैंडओवर करना होगा।
- इस स्टेडियम की क्षमता 30 हज़ार दर्शकों की होगी। स्टेडियम निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होगा।
- विदित है कि हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ विशेषज्ञों ने प्रस्तावित ज़मीन का निरीक्षण भी किया था।

केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर काशी में दौड़ेगी वाटर टैक्सी

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संजय बंधोपाध्याय ने बताया कि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट (सबसे उत्तर) से अस्सी घाट (सबसे दक्षिण) के बीच वाटर टैक्सी भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह टैक्सी वाराणसी के सभी 80 घाटों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलेगी। बीच में इसके लिये चार स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी घाटों पर जलमार्ग प्राधिकरण फ्लोटिंग जेटी उपलब्ध कराएगा। इससे लोगों का टैक्सी में चढ़ना और उतरना आसान हो जाएगा।
- इस वाटर टैक्सी का इस्तेमाल न सिर्फ परिवहन के लिये किया जा सकेगा बल्कि लोग बनारस के खूबसूरत घाटों का नज़ारा भी इससे ले सकेंगे।
- ज्ञातव्य है कि अभी बनारस में क्रूज और कार्गो का संचालन हो रहा है। इसका इस्तेमाल केवल पर्यटक ही करते हैं। लेकिन वाटर टैक्सी का इस्तेमाल बनारस के लोग सड़क पर जाम से छुटकारे के लिये भी कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया।

एएएन अवार्ड 2023 से सम्मानित हुए बीएचयू के दो न्यूरो डॉक्टर

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2023 को चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के दो चिकित्सकों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा एएएन अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आईएमएस बीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक पाठक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आनंद को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित वार्षिक समारोह में एएएन अवॉर्ड 2023 से नवाजा गया।
- न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. विजय नाथ मिश्र ने बताया कि डॉ. अभिषेक पाठक ने लकवा के कारण, बचाव व सतर्कता पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया था।
- वहीं डॉ. आनंद कुमार को यह सम्मान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल सहित कई राज्यों से आने वाले मरीजों में सिरदर्द की समस्या पर शोध कार्य के लिये दिया गया।

नोट :

उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालयों से हटाए जाएंगे सभी पुरुष स्टाफ

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रदेशभर में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी पुरुष स्टाफ को हटाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा महानिदेशक और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पुरुष कार्मिक का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया है।
- उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा का यह कदम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आवासीय सुविधा के साथ कक्षा छह से आठ तक की शिक्षा ग्रहण कर रहीं छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने 12 अक्टूबर, 2022 को पत्र लिखकर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सभी पदों पर महिला कार्मिकों की ही नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में 2023-24 शैक्षणिक सत्र में पुरुष स्टाफ का नवीनीकरण न करने और रिक्त हो रहे पदों पर सिर्फ महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में वार्डेन से लेकर चौकीदार तक सभी कार्मिकों को संविदा पर रखा जाता है। राज्य में कानपुर नगर और औरैया ज़िलों को छोड़कर सभी जिलों के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक कस्तूरबा विद्यालय संचालित है।
- कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में केवल महिला कार्मिकों के नवीनीकरण के आदेश से एक हज़ार से अधिक पुरुष स्टाफ के प्रभावित होने का अंदेशा है।
- प्रदेशभर के 746 विद्यालयों में अधिकांश लेखाकार और चौकीदार पुरुष हैं। कुछ जगहों पर शिक्षक भी पुरुष हैं। ऐसे में प्रत्येक स्कूल पर दो पुरुष कार्मिक का भी अनुमान लगा लें तो डेढ़ हज़ार के आसपास स्टाफ प्रभावित होगा।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच हुआ समझौता

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में आयोजित गन्ना किसानों के वृहद हित लाभ के लिये कार्यशाला में प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच 'सूक्ष्म सिंचाई' पर एक सामान्य दृष्टि और प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिये समझौता हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक की ओर से अजित राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से महासचिव दीपक गुप्तारा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- 2030 डब्ल्यूआरजी ने अपने पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश परियोजना के अंतर्गत 'ड्रिप इरिगेशन' के बारे में एक प्रस्तुति दी। कार्यशाला में मैसर्स गुजरात ग्रीन रेवोलुशन कंपनी (जीजीआरसी), अहमदाबाद ने भी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये विकसित किये जा रहे 'न्यू सिंगल विंडो डिलीवरी मॉडल' को पेश किया और गुजरात के गन्ना किसानों के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। किये गए कार्यों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि गुजरात राज्य में गन्ना किसान लगभग 30 प्रतिशत पानी की बचत करने में सफल रहे।
- विश्व बैंक अपने जल संसाधन समूह और यूपीएसएमए 'यूपी प्रगति एग्री वाटर एक्सेलरेटर' (यूपी प्रगति कृषि जल त्वरक कार्यक्रम) को लागू करने के लिये साथ मिलकर काम कर रहा है।
- यह परियोजना राज्य के गन्ना किसानों के समग्र लाभ के लिये स्थायी 'सूक्ष्म सिंचाई मॉडल' विकसित करने के लिये दो संगठनों की सामर्थ्य का समन्वय करती है। कार्यक्रम वर्तमान प्राथमिकता मानदंड के आधार पर राज्य के 38 से अधिक जनपदों में वृहद स्तर पर सहायता कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है। इससे गन्ना किसानों की उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आने का अनुमान है।

नोट :

- परियोजना मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी-
  - गन्ने की खेती में जल कुशल आचरण को बढ़ावा देना।
  - गन्ने की खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
  - लो कार्बन एर्गोनोमिक संचालन को बढ़ावा देकर चीनी संवर्धन श्रृंखला को डी-कार्बोनाइज करना।
- विदित है कि उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसएमए) उत्तर प्रदेश में निजी चीनी मिलों का एक प्रमुख संगठन है। यूपीएसएमए का मुख्य उद्देश्य सरकार की अनुकूल और विकासोन्मुख नीतियों के माध्यम से प्रदेश में निजी चीनी मिलों के कामकाज और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना है। यूपीएसएमए राज्य में गन्ना किसानों और उद्योग हित में 1938 से कार्यरत है।
- 2030 जल संसाधन समूह, विश्व बैंक समूह का एक सार्वजनिक, निजी, सिविल सोसाइटी मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड है। डब्ल्यूआरजी (WRG) सामूहिक निर्णय लेने और पानी से जुड़े सभी क्षेत्रों में मज़बूत सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले लीक से हटकर (आउट-ऑफ-द-बॉक्स) समाधानों को सह-डिजाइन करने में हितधारकों का समर्थन करता है।

नोट :